



JHS SVENDGAARD RETAIL VENTURES LIMITED

CIN: L52100HR2007PLC093324

To,

September 29, 2026

The Listing Department Bombay Stock Exchange Limited Department of Corporate Services Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street Mumbai – 400001 <u>Scrip Code- 544197</u>	The Listing Department National Stock Exchange of India Limited Exchange Plaza, C-1, Block-G Bandra Kurla Complex Mumbai – 400051 <u>Symbol- RETAIL</u>
--	--

Subject- Newspaper advertisement for Notice of Postal Ballot.

Dear Sir,

Pursuant to Regulation 47 and 30 read with Schedule III, Part A Para A of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 we hereby inform you that the newspaper advertisement regarding the Notice of Postal Ballot dated September 24, 2026 to seek approval from the members of the Company has been published in the Business Standard (English) and Business Standard (Hindi) on September 29, 2026.

The newspaper clippings are enclosed for your information and records.

Thanking You,

For JHS Svendgaard Retail Ventures Limited

**Kuldeep
Jangir**

Digitally signed by
Kuldeep Jangir
Date: 2026.09.29
11:46:03 +05'30'

Kuldeep Jangir
Company Secretary & Compliance Officer

Encl: A/a

 IDBI BANK CIN: L58190MH2004GH14833	नियम 8(1) कच्चा सूचना
8वीं मंजिल, प्लेट-बी, ब्लॉक-2, एनबीसी कार्यालय परिसर, फिदवई नगर (पूर्व),नई दिल्ली-110023, दूरभाष : 011-69297100	
जबकि अयोधस्ताहरी, प्रतिभूतिकरण और वित्तीय आर्थिकों का पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (का 54) के अंतर्गत आईबीबीआई बैंक लिमिटेड के अधिकृत अधिकारी द्वारा के नाते तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(2) के अंतर्गत प्रदात शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिनांक 07.03.2022 को एक मांग सूचना जारी किया था, जिसमें उधारकर्ता श्री सुनील मधुकर राव लाजेवार पूर्व श्री मधुकर एम लाजेवार और श्रीमती भावना गायबने पत्नी स्वामीय श्री सुनील मधुकर राव लाजेवार को नोटिस में उल्लिखित राशि करबे 18,57,403 /- (रुपये अठारह लाख सत्तावन हजार बार सौ तीन पाय) दिनांक 10.05.2021 तक की, उस पर आगे के ब्याज और प्रसार सहित, उक्त नोटिस की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर चुकाने के लिए कहा गया था। उधारकर्ता द्वारा राशि चुकाने में विफल रहने पर, एतद्वारा उधारकर्ता और आम जनता को सूचित किया जाता है कि अयोधस्ताहरी में 24.09.2026 को अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (4) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सुझा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 के साथ पठित, नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा ले लिया है।	
उधारकर्ता द्वारा राशि चुकाने में विफल रहने पर, एतद्वारा उधारकर्ता और आम जनता को सूचित किया जाता है कि अयोधस्ताहरी में 24.09.2026 को अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (4) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सुझा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 के साथ पठित, नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा ले लिया है।	
उधारकर्ता विशेष रूप से और आम जनता सामान्य रूप से एतद्वारा सावधानी की जाती है कि उक्त संपत्ति के साथ कोई लेन-देन न करे और संपत्ति के संबंध में किसी भी प्रकार का लेन-देन आईबीबीआई बैंक लिमिटेड के रु. 18,57,403 /- (रुपये अठारह लाख सत्तावन हजार बार सौ तीन पाय) के प्रसार के अधीन होगा, जो कि 10.05.2021 को उक्त राशि है, साथ ही उस पर आगे का ब्याज और शुल्क भी चुकाए जायें होंगे।	
उधारकर्ता का अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (6) के प्राधान्यों की ओर आकर्षित किया जाता है, जो सूचित परिसंपत्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में हैं।	
संपत्ति का विवरण	
संपत्ति का वह समस्त भाग और पारसु जिसमें प्लेट नं. 906, नौवीं मंजिल, पास अपार्टमेंट्स, कॉसमॉस ग्रीन, निवाडी, राजस्थान 3301019 शामिल है	
उत्तर में: एनए	दक्षिण में: एनए
पूर्व में: एनए	पश्चिम में: एनए
साथ ही उस पर स्थित सभी भवन और संरचनाएं तथा पृथ्वी से जुड़ी या पृथ्वी से जुड़ी किसी वस्तु से स्थायी रूप से बंधी सभी संयंत्र और मशीनरी।	
दिनांक: 24-09-2026 स्थान: नई दिल्ली	हस्ताक्षरित /- , अधिकृत अधिकारी, आईबीबीआई बैंक लिमिटेड,

पंजीकृत कार्यालय के स्थानांतरण की सार्वजनिक सूचना	सूचना
सीमित देयता भागीदारी अधिनियम, 2008 की धारा 13 के साथ पठित एलएनए (एलएनए का निगमन) नियम, 2009 के नियम 17 के अनुसार हम	
और	
आइकॉन मर्जिडाइज एलएलपी के मामले में, जिसका पंजीकृत कार्यालय 2९/106, रंग राखान अपार्टमेंट्स, प्लॉट - 7/4 रोहिणी, उत्तर पश्चिम, नई दिल्ली, दिल्ली 110085 में स्थित है।	
एतद्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि एलएनए, सीमित देयता भागीदारी अधिनियम, 2008 की धारा 13 के अंतर्गत एक सरकार के समक्ष एलएलपी को पंजीकृत कार्यालय को दिल्ली राज्य (अर्थात् कंपनी रजिस्ट्रार, दिल्ली 11) के अधिकारी क्षेत्र से से हरियाणा राज्य (अर्थात् कंपनी रजिस्ट्रार, हरियाणा के अधिकारी क्षेत्र में) स्थानांतरित करने की पुष्टि हेतु आवेदन करने का प्रस्ताव रखती है, जो 18 सितंबर 2026 को आयोजित नामित भागीदारों की बैठक में पारित प्रस्ताव के अनुसार है, ताकि एलएलपी अपने पंजीकृत कार्यालय को "दिल्ली राज्य" से "हरियाणा राज्य" में परिवर्तित कर सके।	
कोई भी व्यक्ति जिसका हित एलएलपी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित परिवर्तन से प्रभावित हो सकेगी संमानना है, वह अपने हित की प्रकृति और विस्तार के आधारों को बताते हुए शपथपत्र द्वारा समर्थित अपनी आपाजोबी संबंधित आरओसी दिल्ली 11 (सिद्ध दिल्ली) डीपी मॉडल, कल नाकक पत्र, जमा मार्केट, नई दिल्ली 110003 को इस नोटिस के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन (21 दिन) के भीतर व्यक्तिगत रूप से दे सकता है या दिल्वा सकता है या पंजीकृत डाक द्वारा भेज सकता है, जिसकी एक प्रति आवेक एलएलपी के पंजीकृत कार्यालय 2९/106, रंग राखान अपार्टमेंट्स, प्लॉट 7/4 रोहिणी, उत्तर-पश्चिम, नई दिल्ली, दिल्ली 110085 पर भेजी जाएगी।	
दिनांक: 29-09-2026 स्थान: दिल्ली	आवेदक की ओर से एवं के लिए आइकॉन मर्जिडाइज एलएनपी हस्ताक्षरित /- सुरेंद्र जीतानी (सं: 02168155) नामित भागीदार

RBL BANK

apna ka bank

आरबीएल बैंक लि.

राष्ट्रीय परिवर्तन केंद्र: अमी मॉडल रोड, सावकर पहाड़ीओर के पास, गोरगांव (पश्चिम) मुंबई - 400062

मुख्य कार्यालय: एचडीएफसी बैंक इंडिया *Head Office* इंदौर, सेनापति बागट मारंग, लोखर पल्ल (परिणाम) मुंबई – 400 013, क्षेत्रीय कार्यालय **एचडीएफसी बैंक लिमिटेड**, विशेष परिवर्तित नियम, मूलतः गुलाम नगर, 6, बन्दरपुर शाह जकर मारंग, आईटीओ, नई दिल्ली 110002

स्वर्ण नीलामी सह आर्थिक प्रवर्तन

नीचे उल्लिखित उधारकर्ता को आरबीएल बैंक लिमिटेड से उनके द्वारा प्राप्त स्वर्ण आभूषणों के बदले ऋण सुविधा ("सुविधा") के लिए बकाया राशि का भुगतान करने के लिए मांग नोटिस भेजा गया है। चूंकि उधारकर्ता सुविधा के तहत बकाया चुकाने में विफल रहा है, इसलिए हम **07.10.2026** को गिरवी रखे गए सौने के आभूषणों की नीलामी करने के लिए बाध्य हैं। यदि इस नीलामी से कोई अतिरिक्त राशि प्राप्त होती है, तो उसे संबंधित उधारकर्ता को वापस कर दिया जाएगा और यदि नीलामी के बाद कोई घाटा होता है, तो शेष राशि उधारकर्ता से उचित नीलामी कार्यवाही के माध्यम से वसूल की जाएगी। आरबीएल बैंक को बिना किसी पूर्व सूचना के निम्नलिखित खाते को नीलामी से हटाने का अधिकार है। इसके अलावा, आरबीएल बैंक बिना किसी पूर्व सूचना के नीलामी की तारीख बदलने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

क्र. सं.	खाता नं.	शाखा का नाम	कर्जदार का नाम	सौने के आभूषण का विवरण (ग्राम में)	
1.	8090110030656	सेक्टर 21सी, फरीदाबाद	सुशीला	कुल सकल वजन कुल असुद्धता कुल स्टीन वजन कुल निवल वजन	18.7 0.37 0 18.326
2.	8090110931461	कमला नगर	प्रवीण कुमार	कुल सकल वजन कुल असुद्धता कुल स्टीन वजन कुल निवल वजन	5.87 0.17 1.4 4.3
3.	8090909065481	तिलक नगर	वेद प्रकाश पांडे	कुल सकल वजन कुल असुद्धता कुल स्टीन वजन कुल निवल वजन	7.7 0.60 0 7.1
4.	809011403886	भेरा एन्क्लेव पश्चिम	बबीता रानी	कुल सकल वजन कुल असुद्धता कुल स्टीन वजन कुल निवल वजन	302.7 9.85 29.6 263.25
5.	8090110998262	सेक्टर 21सी, फरीदाबाद	सुशीला.	कुल सकल वजन कुल असुद्धता कुल स्टीन वजन कुल निवल वजन	9.34 0.34 0 9
6.	809011802892	करोल बाग	अनिशा दाका	कुल सकल वजन कुल असुद्धता कुल स्टीन वजन कुल निवल वजन	198.9 4.90 56 138
7.	809012220800	सेक्टर 21सी, फरीदाबाद	देव राज	कुल सकल वजन कुल असुद्धता कुल स्टीन वजन कुल निवल वजन	101.96 6.26 0 95.7
8.	809012222330	सफदरजंग एन्क्लेव	कुलजीत सिंह	कुल सकल वजन कुल असुद्धता कुल स्टीन वजन कुल निवल वजन	109.5 2.30 0 107.2
9.	8090121106096	नोएडा सेक्टर 77	जीतेंद्र यादव	कुल सकल वजन कुल असुद्धता कुल स्टीन वजन कुल निवल वजन	5.2 0.30 0 4.9
10.	809011856486	नोएडा सेक्टर 77	जीतेंद्र यादव	कुल सकल वजन कुल असुद्धता कुल स्टीन वजन कुल निवल वजन	5 0.30 0 4.7
11.	809012221340	सेक्टर 21सी, फरीदाबाद	मयंक भड़ाना	कुल सकल वजन कुल असुद्धता कुल स्टीन वजन कुल निवल वजन	37.16 2.76 0 34.4
12.	809012704667	गुजरगवाला, मॉडल टाउन	धीरेन्द्र प्रताप सिंह	कुल सकल वजन कुल असुद्धता कुल स्टीन वजन कुल निवल वजन	154.3 3.30 44 107
13.	809012402404	डीडी गुप्ता रोड, दिल्ली	मनोज कुमार	कुल सकल वजन कुल असुद्धता कुल स्टीन वजन कुल निवल वजन	93.7 3.20 27 63.5
14.	809012385763	अल्हा-1	ऋषभ नगर	कुल सकल वजन कुल असुद्धता कुल स्टीन वजन कुल निवल वजन	26.5 1.40 0 25.1

ऑनलाइन नीलामी <https://legold.auctiontiger.net> या <https://blegold.auctiontiger.net> पर 07-10-2026 को दोपहर 02:00 बजे से शाम 05:00 बजे तक आयोजित की जाएगी। इच्छुक व्यक्ति/व्यक्तियों से ई-प्रोक्योरमेंट टेनोनीलीजीज लिमिटेड (ऑक्शनटाइगर) से 0351899640 / 79842129853 पर संपर्क करें। विस्तृत नियम और शर्तों के लिए, कृपया नीलामी पोर्टल पर जाएं।

स्थान: दिल्ली
तिथि: 29.09.2026

प्राधिकृत अधिकारी
आरबीएल बैंक लि.

FEDBANK	फेडबैंक फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालय: यूनिट नं.: 1101, 11वीं मंजिल, सिमनर, प्लॉट नं. 71 ए, पवई, पासपोली, मुंबई – 400 087	
अचल संपत्तियों की नीलामी सह विक्रय हेतु सार्वजनिक सूचना	
सुरक्षित परिसंपत्तियों के विक्रय की 30 दिनों की सूचना एतद्वारा सुरक्षित ऋणदाता फेडबैंक फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड द्वारा, वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा सुझा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 तथा सुझा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) एवं 9(1) के साथ पठित प्राधान्यों के अंतर्गत हस्तांतरणकर्ता, सुरक्षित ऋणदाता के अधिकृत अधिकारी के रूप में, सारफेसी अधिनियम, 2002 के तहत सुरक्षित परिसंपत्ति का कब्जा कर लिया है।	
इसके द्वारा आम जनता को तथा विशेष रूप से उधारकर्ताओं / सह-उधारकर्ताओं / गारंटरों को यह सूचना दी जाती है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति, जो सुरक्षित ऋणदाता, फेडबैंक फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड को गिरवी रखी गई है, / प्रभारित की गई है, जिसका कब्जा फेडबैंक फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, सुरक्षित ऋणदाता के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ले लिया गया है, के रूबी जनरल स्टोर (उधारकर्ता), रुक्मिणी रुक्मणी (सह-उधारकर्ता), मानु प्रताप सिंह (सह-उधारकर्ता), राजेंद्री राजेंद्री (सह-उधारकर्ता) से फेडबैंक फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, सुरक्षित लेनदार की कुल बकाया राशि रु. 1,26,22,406/- (रुपये एक करोड़ छब्बीस लाख बाईस हजार चार सौ छह मात्र) दिनांक 06.07.2026 तक अर्थात्, रु. 1,02,76,134 /- (रुपये एक करोड़ दो लाख छिहतर हजार एक सौ सौतीस मात्र) ऋण खाता संख्या FEDNOILAP0544535 में और रु. 23,46,272 /- (रुपये तेईस लाख छियालीस हजार दो सौ बहतर मात्र) ऋण खाता संख्या FEDNOILAP0546360 में, और दिनांक 07.07.2026 से उस पर ब्याज, एवं इवई इत्यादि सहित की वसूली हेतु "जैसा है, जहां है", "जैसा है, जो है" तथा "जहां भी है" के आधार पर दिनांक 06.11.2026 को सुबह 10 बजे से 10.30 बजे बेचा जाएगा।	
अचल संपत्ति का विवरण	
बंबक संपत्ति के समस्त भाग एवं खण्ड जोकि प्लॉट नंबर सी-71, भूतल, खसरा नं. 13/3 सी ब्लॉक, एरिया 154.68 वर्ग मी., पटेल गार्डन एक्सप्रेसवेन, नजफगढ़ रोड, काकरोला मोड़, दिल्ली-110078, सीमाएं: पूर्व – 20 फीट चौड़ी गली, पश्चिम – 20 फीट चौड़ी सड़क, उत्तर – 25 फीट चौड़ी सड़क, दक्षिण – अन्य का प्लॉट	
आश्चित मूल्य (रु. में)	रु. 2,85,00,000 /- (रु. दो करोड़ पैसठ लाख मात्र)
बराना राशि जमा (रु. में) – DD/PORTRGS के माध्यम से	रु. 28,50,000/- (रु. छब्बीस लाख पचास हजार मात्र)
फेडबैंक फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के पक्ष में	
बोली में वृद्धि की राशि	रु. 50,000 /- (रु. पचास हजार मात्र)
ईएमडी के साथ सीलबंद प्रस्ताव /निविदा के रूप में बोलियाँ जमा करने की अंतिम तिथि, समय और स्थान	05 नवम्बर 2026 को शाम 05:00 बजे तक फेडबैंक फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, पत्नी, कीर्ति नगर मेट्रो स्टेशन के सामने, 2A/8A, 63, रामा रोड, दिल्ली, 110015
संपत्तियों का निरीक्षण	30 अक्टूबर 2026 शाम 5 बजे से पूर्व
पुष्टि किए गए सफल बोलीदाता के लिए स्वीकृत उच्चतम बोली की 25% राशि (ईएमडी सहित) के भुगतान की अंतिम तिथि	भुगतान बोली की पुष्टि की तारीख से अगले कार्य दिवस तक किया जाना चाहिए
उच्चतम बोली की शेष 75% राशि के भुगतान की अंतिम तिथि	बोली की पुष्टि की तारीख से 15 दिनों के भीतर

विक्रय की विस्तृत शर्तों एवं नियमों के लिए कृपया सुरक्षित ऋणदाता फेडबैंक फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड (फेडफिना) की वेबसाइट www.fedfina.com पर उपलब्ध किए <https://www.fedfina.com/public-notice-for-auction-cum-sale/under> को देखें। किसी भी प्रकार की पुश्तछा, जानकारी, सहायता, प्रक्रिया एवं प्रशिक्षण हेतु कृपया फेडबैंक फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के अधिकृत अधिकारी श्री ओमकार रौजिज, 9664323822, ईमेल आईडी: omkar.redji@fedfina.com और श्री दश क्वात्रा-9994989043, ईमेल आईडी: daksh.kwatra@fedfina.com श्री चमन लाल-8447272883, ईमेल आईडी: chaman.lal@fedfina.com से संपर्क करें। सुरक्षित परिसंपत्तियों को मुक्त करने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में आपका ध्यान सारफेसी अधिनियम, 2002 की धारा 13 की उपधारा (8) के प्राधान्यों की ओर भी आकर्षित किया जाता है।

(प्राधिकृत अधिकारी)

फेडबैंक फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड

कच्चा सूचना (अचल संपत्ति हेतु)	
जब कि, इंडिया एसएमई एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (आईएसआरसी) (CIN: U67190MH2008 PLC181062) प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते अयोधस्ताहरी ने सिस्कोरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फार्मानशियल असेट्स एंड एम्प्लोमेंट ऑफ सिस्कोरिटी इंटेरेस्ट एक्ट, 2002 के अंतर्गत और नियम 3 के साथ धारा 13(2) के साथ सिस्कोरिटी इंटेरेस्ट (एम्प्लोमेंट) रूप, 2002 के साथ पढ़ते हुए प्राप्त अधिकारों का उपयोग करके कर्जदार आरुष उपाध्याय (स्वामी अजीत कुमार उपाध्याय और सीमा उपाध्याय के पुत्र और कानूनी वारिस) को 08.07.2026 के सूचना में वर्णन के अनुसार कर्ज खाना नं. HHLNOD00423965 की राशि रु. 24,21,277/- (रुपये चौबीस लाख इक्कीस हजार दो सौ सतहतर मात्र) और 30.06.2026 के अनुसार उस पर ब्याज उक्त सूचना की प्राप्ति की तारीख से स्पष्ट 60 दिनों के भीतर चुकता करने का आवाहन करते हुए अधिवाचना सूचना जारी की थी। धनराशि चुकता करने में कर्जदारों के असफल रहने पर एतद्वारा कर्जदार और सर्व सामान्य जनता को सूचना दी जाती है कि, अयोधस्ताहरी ने उक्त कानून की धारा 13 की उप-धारा 4 के साथ उक्त कानून के नियम 8 के तहत सिस्कोरिटी इंटेरेस्ट (एम्प्लोमेंट) रूप, 2002 के तहत प्राप्त अधिकारों का कार्यान्वयन करके 24.09.2026 को संपत्ति पर सांकेतिक अधिपत्य कर लिया है। विशेषतः कर्जदारों(ओं) और सामान्यतः जनता को एतद्वारा संपत्ति के साथ सीधा नहीं करने के लिए सावधान किया जाता है और संपत्ति के साथ कोई भी सौदा राशि रु. 24,21,277/- (रुपये चौबीस लाख इक्कीस हजार दो सौ सतहतर मात्र) 30.06.2026 के अनुसार और उस पर ब्याज के साथ इंडिया एसएमई एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड के अधीन होगा। उधारकर्ताओं का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के अन्तर्गत संपत्ति / संपत्तियों को मुक्त करने के लिए उपलब्ध समय की ओर आकर्षित किया जाता है।	
अचल संपत्ति का विवरण	
मकान नं. डी-104, क्षेत्रफल 38.018 स्क्वे मीटर्स , भूतल, पहली मंजिल और दुसरी मंजिल, कुल कवर्ड क्षेत्र 95.04 स्क्वे मीटर्स , इन के अधिकार के साथ, सेक्टर-23 पर स्थित , ब्लॉक- "डी", आवासिय कॉलोनी, संजय नगर, महलील और जिला गाज़ियाबाद -201010, उत्तर प्रदेश और जिसकी सीमाएं निम्नानुसार परिक्रदैः हैं: पूर्व : मकान न.105 पश्चिम : मकान नं. 103 उत्तर : मकान नं.101 दक्षिण : 25 फीट चौड़ी सड़क	
दिनांक : 24.09.2026 स्थान : गाज़ियाबाद	सही/- प्राधिकृत अधिकारी इंडिया एसएमई एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड आईएसआरसी-2025-2026-5 ट्रस्ट के ट्रस्टी के के रूप में कार्यरत

JHS JOINT HSE	जेएचएस स्वेन्हागर्ड रिटेल वेंचर्स लिमिटेड
सीआईएन : L52100HR2007PL.C093324	
पंजीकृत कार्यालय : धावला तल, प्लॉट नंबर 107, सेक्टर-44 इन्स्ट्रुक्शनल एरिया, नुक्रामा, हरियाणा, भारत, 122001	
फोन नंबर : 011-40539487 फैक्स नंबर : 011-26900434	
वेबसाइट : www.jhsretail.com ईमेल : cs@jhsretail.com	
डाकीय मतदान की सूचना	
एतद्वारा सदस्यों को सूचित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के साथ पठित धारा 110 और लागू लागू कानूनों, यदि कोई, के साथ पठित मामलों (प्रबंधन और प्रशासन) नियमावली, 2004 के नियम 22 और नियम 20 के साथ पठित, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी दिनांक 8 अप्रैल 2020, 13 अप्रैल 2020, 25 सितंबर 2023, 19 सितंबर 2024 और 22 सितंबर, 2025 के सामान्य परिपत्रों, सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमावली, 2015 और भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सामान्य बैकवॉ के पर सचिवीय मानक (एसएस-2), यथा संशोधित के अनुसार में, कंपनी ने डाकीय मतदान सूचना में वर्णितानुसार विशेष व्यवसाय की आइटम पर विशेष प्रस्ताव पारित करने द्वारा, कानी के सदस्यों से इलेक्ट्रॉनिक विधि से डाकीय मतदान (रिमोट ई-वोटिंग) द्वारा सीक्रेटि प्राव करने के लिए केवल कंपनी के उन सभी सदस्यों को डाकीय मतदान सूचना का इलेक्ट्रॉनिक प्रेषण दिनांक 24 सितंबर, 2026 को पूरा कर लिया है, जिनका ईमेल पता कंपनी/डिजिटल रिटेल प्रिमागी (डी) के साथ शुक्रवार, 25 सितंबर 2026 ("कट-ऑफ डेट") को पंजीकृत है। कानी ने सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक विधि से वोट डालने के लिए रिमाट ई-वोटिंग की सुविधा देने के लिए नेगेशन सिक्वीरिडिगिटीज लिमिटेड ("एनएससीएल") की सेवाएं अनुबंधित की हैं। रिमोट ई-वोटिंग की विस्तृत प्रक्रिया डाकीय मतदान की सूचना में दी गई है। रिमोट ई-वोटिंग की अवधि मंगलवार, 29 सितंबर, 2026 को सुबह 9:00 बजे (आईएसटी) आरंभ होगी और बुधवार, 29 अक्टूबर, 2026 को शाम 5:00 बजे (आईएसटी) समाप्त होगी। तदुपरांत, एनएससीएल रिमोट ई-वोटिंग मीज्यूल् को बंद कर देगा और डिजिटल रिटेल को बंद ई-वोटिंग की अनुमति नहीं होगी। एक बार जब सदस्य प्रस्तावों पर अपना वोट डाल देंगे, तो उन्हें बाद में इसे बदलने की अनुमति नहीं होगी। केवल वे सदस्य, जिनके नाम कानी के ई-वोटिंग तिथि तब कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर पर डिजिटलिंग द्वारा बनाए गए लाभार्थी चरमियों के रजिस्टर में दृष्टिगत हैं, प्रस्तावों पर अपना वोट डालने के हक्कदार हैं। यह सूचना कंपनी (www.jhsretail.com), नेगेशन स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (www.nseindia.com), बीएसई लिमिटेड (www.bseindia.com), और एनएससीएल (www.evoting.nsdl.com) की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है।	
इस अवधि में, कंपनी के सदस्य, जिनके पास 25 सितंबर 2026 की कट-ऑफ तिथि तक मौतिक या डीमैट रूप में शेयर हैं, वे रिमोट ई-वोटिंग से अपना वोट डाल सकते हैं और जो व्यक्ति कट-ऑफ तिथि तक शेयर नहीं है, वे इस सूचना को केवल जानकारी के लिए निमित्त समझें। जिन सदस्यों के पास मौतिक/इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयर हैं और उनके ई-मेल एड्रेस कंपनी/उनके संबंधित डिजिटल रिटेलिंग के साथ पंजीकृत नहीं हैं, उनसे अनुरोध है कि वे स्वस्थानीय फॉर्म आईएसआर-1 (कंपनी की वेबसाइट www.jhsretail.com पर उपलब्ध) और समर्थन दरतावेत कंपनी में जमा करके अपने ई-मेल एड्रेस पंजीकृत करें। डीमैट रूप में शेयर धारक सदस्य अपने डिजिटल रिटेलिंग पॉर्टलसिड के साथ अपना ईमेल एड्रेस अद्यतन कर सकते हैं।	
कंपनी के निदेशक मंडल ने मैसर्स दक्षिण एंड एशियासिड्स, प्रैक्टिसिंग कानूनी सेक्रेटरी के पार्टनर, श्री मोहित दाहिया (एच.एच. 230552) को डाकीय मतदान ई-वोटिंग की निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से जांच करने के लिए संपीक्षक नियुक्त किया है। संपीक्षक ई-वोटिंग की जांच पूरी होने के बाद अपनी रिपोर्ट चैयरमैन या चैयरमैन द्वारा अधिकृत किसी अन्य व्यक्ति को जारी करेगा, और परिणाम ई-वोटिंग समाप्त होने के दो कार्य दिवसों के अंदर घोषित किए जाएंगे, और वे परिणाम निम्न हैं, प्रस्तावों का अनुसरण करें इंडिया लिमिटेड (www.nseindia.com), बीएसई लिमिटेड (www.bseindia.com), और एनएससीएल (www.evoting.nsdl.com) की वेबसाइट पर भी उपलब्ध किए जाएंगे।	
इलेक्ट्रॉनिक विधि से वोटिंग संबंधी किसी भी संदेह या शिकायत के लिए, सदस्यध्या www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड अवराम में मौजूद श्रेयहोल्डर्स के लिए अनुरोध पूछे जाने वाले सवाल (एफएक्यूज) और शेयहोल्डर्स के लिए ई-वोटिंग यूजर मैनुअल देख सकते हैं या 1800-1020-990 और 1800 2244 30 पर कॉल कर सकते हैं अथवा यूजी प्लव्ही नहीं है, सीनियर मैनेजर, एनएससीएल, चार्टर्ड ए" ए" लिग, ट्रेड वॉचर, कानून मिल्स कंपाउंड, सेनापति बागट मारंग, लोखर परेड, मुंबई – 400 013 से नामित ईमेल आईडी : evoting@nsdl.co.in पर संपर्क कर सकते हैं, जो रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा से जुड़ी शिकायतों को भी दूर करेगी।	
नियेशक मंडल के आदेश द्वारा	
हस्ता./- 	कुसुमिणी जोगिड़ कंपनी सेक्रेटरी
दिनांक : 29-09-2026 स्थान : नई दिल्ली	

आधार हाउसिंग फायनेंस लिमिटेड

कांपीरेट कार्यालय: ऑफिस नं. 501 एवं 503, पॉचवी मंजिल, लाइटब्रिज, साकी विहार रोड, अंधेरी ईस्ट, मुंबई सुबुर्बन (जिला), महाराष्ट्र-400072

मुरादाबाद शाखा – शाप नं. 6, पहली मंजिल, पित्तल कॉन्प्लेक्स, प्रिंग फ़िल्ड के सामने, दिल्ली रोड, मुरादाबाद – 244001 (उ.प्र.)

आगरा शाखा: कार्यालय नं. 504, पॉचवी मंजिल, बिजनेस स्क्वायर, ब्लॉक-ई-15/8, संजय प्लेस, आगरा-282002 के पास.

अलीगढ़ शाखा: कार्यालय नं. 305, 306 एवं 307, द्वितीय तल,

OPINION

A power warning India needs to heed

ABHISHEK ANAND, PRAVEEN RAVI,
NAVNEERAJ SHARMA AND
ARVIND SUBRAMANIAN

Is the era of increasingly uninterrupted power over? September 2026 should be a wake-up call for India's electricity sector. In the wake of three adverse shocks — the war on Iran, a weak monsoon and warmer nights — the system has coped, but the signals are flashing amber, perhaps even red. Consider the success, warning and lesson.

Success. Renewables have helped cope with surging demand. Since Covid, average and peak electricity demand have grown annually at about 8 per cent. In the wake of the three shocks, between April 1 and September 20, the average daily electricity supplied increased by 10.5 per cent over the same period in 2025 and peak demand that was met rose by 11.8 per cent. Creditably, the system stepped up.

Renewables were key to meeting this increased demand. Wind and solar capacity have been increasing over the last few years but in this year of stress they played an especially important role.

Between April 1 and September 20, wind and solar supplied 18.3 per cent of the electricity delivered through the grid, up from 15.9 per cent a year earlier. But as Figure 1 shows, they met about three-quarters of the midday increase in demand, although only a fifth of the evening increase.

More broadly, India's demand peaks in the afternoon and late evening. Solar has eased the former even to the extent that prices in solar hours ran below last year's from April to August, although in September 1-20 they more than doubled from ₹1.4 to ₹3.1 per unit. Evening peaks and winter's shorter solar window continue to pose a challenge. Darkness not at noon will require a different solution.

Warning. The return of load-shedding aka power shortage. There are few quainter euphemisms of Indian bureaucracy than "load-shedding." A civil engineer whose bridge collapses would hardly report a successful reduction in traffic. Yet disconnecting consumers can pass for balancing electricity demand and supply. Power cuts protect the grid but are a failure of service, short-changing citizens. Indeed, these are rising, threatening to become a charged political issue. From Punjab to Kerala, Maharashtra to Tamil Nadu and Karnataka,



PHOTO: SHUTTERSTOCK

policymakers and opposition leaders have issued warnings, and citizens' protests are rising.

In other words, the flip-side of the success, namely meeting rising demand, has been the shortfall in meeting all the demand. Official figures put the evening shortfall at more than four times last year's between April 1 and September 20, and at almost nine times in the first 20 days of September. It is not that in the last decade all consumers have received 24x7 uninterrupted power. But shortages were less of an issue because the direction of improvement was positive. Recently, that has been changing.

Reliable public data on true shortages is not readily available. One, albeit imperfect, proxy of true power availability is to look at Google searches for reports of power cuts. We sum Google search interest in 49 power-cut terms across 12 Indian languages, week by week on one common scale. As Figure 2 shows, searches this year have run well above the previous three years, peaking in the May heatwave and rising again in early September. The burden also falls unevenly. Villages were never on a round-the-clock baseline to begin with — rural feeders, households included, are scheduled fewer supply hours than

towns — and this summer's cuts ran far longer in villages than in cities. Hence the rising grievances.

We have other measures of scarcity. The power exchange is a market for balancing marginal demand and supply and is used by the utilities as such. During September 1-20, average sell orders during the evening peak on IEX's day-ahead market collapsed from 7.5 GW to 1.3 GW per block, reflecting scarcity.

An indicator of system precarity is the frequency at which the grid operates. There is typically a band — 49.90 to 50.05 Hz — within which the grid must operate to preserve its physical health. Between September 1 and 20, the frequency was below 49.90 Hz for 30 per cent of the evening hours, up from 11 per cent a year earlier; on the worst evening, September 15, it was below the band for more than two-thirds of the time. As Figure 3 shows, evenings have not spent this much time below the band since the coal crisis of April 2022.

In sum, a variety of indicators suggest serious shortfalls in supply, rising prices, grid stress and consumer distress. One consequence will be that most discoms will show deteriorating financial performance because costs have gone up while prices have remained unchanged.

State government finances will take a corresponding hit because effective subsidisation will have risen.

Lesson. Shocks are no longer shocks. Policy-makers might dismiss this as an abnormal year. The beckoning complacency would be a grave mistake. The long-run capability of the electricity sector must improve if India has any hopes of becoming an electrostate that is internationally competitive. But climate change and geopolitical uncertainty mean that demand will be continually buffeted. Shocks will be a feature, not a bug, and while technology in the form of improved battery storage will help, it will not be a panacea.

The truth is this: India's electricity distribution system has been in trouble for some time and is approaching crisis levels because of years of under-investment, poor management, perverse incentives, and disastrously inefficient and costly populism. The success of renewables has obscured these fundamentals. And while there are some good apples, most state governments are culpable, with many richer states' electricity systems probably faring worse than others'.

Our earlier work shows how mistargeted subsidies benefit better-off consumers while shifting costs to businesses and future taxpayers. Repeated bailouts have created a moral hazard: Passing losses to future taxpayers blunts the consequences of poor management.

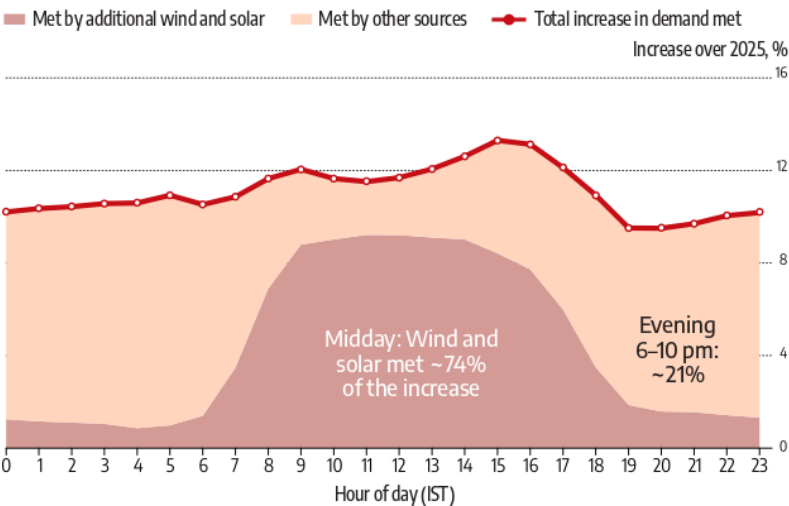
States must now act on a war footing: Publish data on outages, improve demand forecasts, stress-test contingency and resource adequacy plans, secure evening supply, invest in networks, focus on solutions like smart metering, time-of-day tariffs and enforce management accountability. Operational improvements can begin now; durable reform requires sustained investment and institutional work over several years. This cannot be fixed in one or two summers.

At the same time, the Centre too must step in because the actions and inactions of state governments create a national problem. It must ruthlessly tighten budget constraints on state governments by conditioning support on upfront reforms.

In the next round of state elections from Punjab and Uttar Pradesh to Karnataka, power could well become a defining issue. Without action, politi-

Increase in demand met, by hour of day

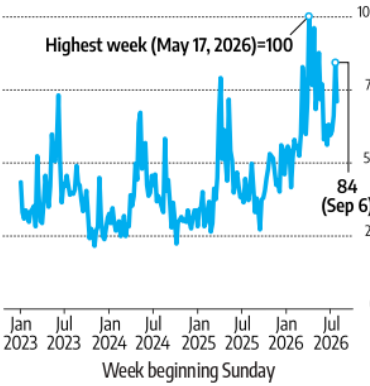
(April 1–September 20, 2026 over same period in 2025)



Source: Grid-India 15-minute transmission-grid snapshots

Google searches for power cuts

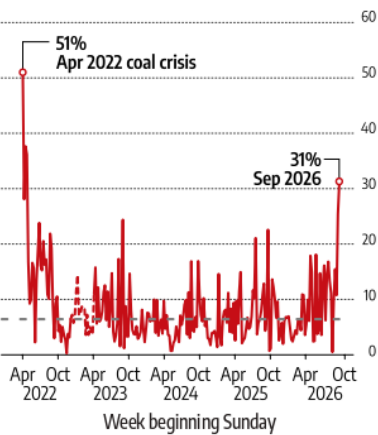
(Index: May 17-23=100)



Note: Google Trends, India, weekly, Jan 1, 2023 to September 19, 2026 (full weeks only); 49 search terms for power cuts in 12 languages (English, Hindi, Bengali, Tamil, Telugu, Kannada, Malayalam, Marathi, Gujarati, Punjabi, Odia, Urdu), rescaled onto one common scale and summed

System precarity

Share of each week's evening hours (6–10 pm) with grid frequency below 49.90 Hz



Source: Grid-India daily frequency profile. Mid-December 2022 to March 2023 data is estimated. Grey dashed line: The median measured week

cians and citizens in India could be singing exasperatedly, "Hello darkness, my old friend. Why have you come to stalk me again?" (with due apologies to Paul Simon and Art Garfunkel).

(The analysis, not the writing, in this piece is based on extensive use of AI)

Abhishek Anand is visiting fellow, Madras Institute of Development Studies; Praveen Ravi is principal consultant, CEGIS; Navneeraj Sharma is an independent consultant; and Arvind Subramanian is senior fellow, Peterson Institute for International Economics

TATA POWER
(Contracts Department)
Jojobera Generation Plant, RAHARGORAH, JAMSHEDPUR-831016, Jharkhand

NOTICE INVITING EXPRESSION OF INTEREST

The Tata Power Company Limited invites expression of interest from eligible vendors for the package Name.

S.No.	Tender Description	Ref No
1	Water sprinkling on Plant Road FY-28 at Tata Power, Jojobera Division	CC27MAKJOJO-02
2	Prefab Office construction at KPO Unit # 4 Project (IEL Kalinga Nagar)	CC27SMJOJO-03
3	Supply and Installation of CCTV infrastructure at PH-7 (IEL Jamshedpur)	CC27SMJOJO-04
4	Procurement of Pulleys for Coal Handling Plant, Tata Power, Jojobera Division	CC27SPJOJO-03

For details of pre-qualification requirements, bid security, purchasing of tender document etc., please visit Tender section of our website (URL: <https://www.tatapower.com/tender>). Eligible vendors willing to participate may submit their expression of interest along with the tender fee for issue of bid document latest by **12th October-2026**.

TATA POWER
Corporate Contracts Department, 5th Floor Station B)
Tata Power, Trombay Thermal Power Station Chembur-Mahul, Mumbai 400074, Maharashtra, India.
(Board Line: 022-67175125, Mobile: 9641867435) CIN: L28920MH1919PLC000567

NOTICE INVITING TENDER

The Tata Power Company Limited invites tender from eligible vendors for the following package.

Fire door installation work at Bhira HPS (CC27SPS107)
Interested and eligible bidders to submit Tender Fee and Authorization Letter before **1500 hrs. of 15th October 2026**. For detailed NIT, please visit Tender section on website <https://www.tatapower.com>. Also, all future corrigendum's if any, to the said tender will be published on Tender section of above website (**Tata Power > Business Associates > Tender Documents**) only.

BEFORE THE NATIONAL COMPANY LAW TRIBUNAL BENCH AT CHENNAI
CP (CAA)/ 76 /CHE/2026
IN
CA (CAA)/ 45 /CHE/2026
In the matter of the Companies Act, 2013
AND
In the matter of Sections 230 to 232 and other applicable provisions of the Companies Act, 2013
AND
In the matter of Scheme of Amalgamation between
ADI BPO Services Limited and MPS Limited and their respective Shareholders and Creditors.
MPS Limited,
A company incorporated under Companies Act, 1956, having its registered office at, Block-B6, 3rd Floor, Gateway Office Parks, No. 16, G.S.T Road, Perungalathur, Chennai, Tambaram, Kanchipuram, Tamil Nadu-600063
...Petitioner /Transferee Company
NOTICE
Notice is hereby given that by an order dated 16th of September 2026, the Chennai Bench of the National Company Law Tribunal has fixed the date of hearing of the Company Petition filed by the Petitioner Companies under Section 230 to 232 of the Companies Act, 2013 for the sanction of Scheme of Amalgamation between ADI BPO Services Limited ("Transferor Company") and MPS Limited and their respective Shareholders and Creditors, on the 04th of November 2026. Any person desirous of supporting or opposing the said Petition should send to the Petitioner's Advocates notice of his intention, signed by him or his Advocate, with his name and address, so as to reach the Petitioner's Advocates not later than two days before the date fixed for hearing of the Petition. Where he seeks to oppose the Petition, the grounds of opposition or a copy of his affidavit shall be furnished with such notice. A copy of the Petition will be furnished by the undersigned to any person requiring the same on payment of the prescribed charges for the same.
Dated this 28th day of September, 2026

PAWAN JHABAKH
Counsel for the Petitioner
New No. 115, First Floor, Luz Church Road,
Mylapore, Chennai – 600004

HDFC Bank Limited
Registered Office: HDFC Bank House, Senapati Bapat Marg, Lower Parel (W), Mumbai 400 013
(CIN: L65920MH1994PLC080618) [E-Mail: shareholder.grievances@hdfc.bank.in] [Website: www.hdfc.bank.in] [Tel No.: 022 6631 6000]

Special window for transfer and dematerialisation of physical shares of HDFC Bank Limited

Pursuant to SEBI Circular No. HO/38/13/11(2)2026-MIRSD-POD/ /3750/2026 dated January 30, 2026, all shareholders are hereby informed that a Special Window is open for a period of one year, from February 5, 2026 to February 4, 2027 to facilitate transfer and dematerialisation of physical securities which were sold/purchased prior to April 01, 2019. The said special window is also available for such transfer requests which were submitted earlier and were rejected/returned/not attended to due to deficiency in the documents/process/otherwise. Further, the securities so transferred shall be mandatorily credited to the transferee only in demat mode and shall be under lock-in for a period of one year from the date of registration of transfer. Such securities shall not be transferred/lien-marked/pledged during the said lock-in period.

Investors are encouraged to take advantage of this opportunity by furnishing the necessary documents to the Bank's Registrar and Transfer Agent i.e. Datamatics Business Solutions Limited at Plot Nos. A 16 & 17, Part B Cross Lane, MIDC, Andheri East, Mumbai 400093.

For HDFC Bank Limited
Sd/-
Ajay Agarwal
Company Secretary
Group Head - Secretarial & Group Oversight
Membership No. FCS 9023

Place: Mumbai
Date: September 28, 2026

MEET THE SPEAKER

CA Rachana Ranade
Stock Market & Finance Educator

Business Standard
Smart Investor
Arena

26–28 October 2026

Jio World Convention Centre, Mumbai

Register now